

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 418/2006

कैलाशचन्द्र शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थांगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.06.2006

आदेश की दिनांक : 03.05.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थांगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड-III के पद पर आदेश दिनांक 22.12.1983 (अनुलग्नक-1) के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.12.1983 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ढाणी अहिरान, सांभरिया पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर में कार्यभार ग्रहण किया गया। जिला परिषद जयपुर के द्वारा आदेश दिनांक 28.11.1990 पारित कर अपीलार्थी की नियुक्ति 31.12.1995 से पूर्व की होने के कारण एवं निरंतर कार्यरत, निर्धारित योग्यता एवं आयु सीमा के अंतर्गत होने से सेवाएं नियमित किये जाने के आदेश पारित किये। जिसमें अंकित किया कि अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ 01.01.1986 से देय हुआ है। प्रत्यर्थांगण द्वारा प्रत्यर्थांगण द्वारा वरिष्ठता सूची दिनांक 22-3-2005 को जारी की गई। उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 484 पर अंकित किया गया जबकि अपीलार्थी के समान दिनांक 22-12-1983 को नियुक्त अन्य अध्यापक तृतीय श्रेणी श्री रामकल्याण शर्मा का नाम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 9 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थांगण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से या अपीलार्थी के साथ

नियुक्त अध्यापक के समान वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जावे। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में अपील संख्या 890/2005 कैलाश चन्द्र शर्मा बनाम निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व अन्य माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय अधिकरण द्वारा उक्त अपील को दिनांक 9-9-2005 को निस्तारित कर दिया गया जिसमें अंकित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग एवं राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। सरकार एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निर्णय लिये जाने के पश्चात ही निर्णय से व्यर्थित होने के पश्चात छह माह की अवधि में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अपरिपक्व अवस्था में अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण एवं संधारण योग्य नहीं होने के आधार पर अस्वीकार कर अपीलार्थी को वापस लौटा दी गई अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 9-9-2005 की पालना में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 19-4-2006 को किया गया। आदेश दिनांक 19-4-2006 में विभाग द्वारा अंकित किया गया कि दिनांक 28-11-1990 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद जयपुर में स्क्रीनिंग कर सेवाएं नियमित की गई है। अतः सेवा को दिनांक 28-11-1990 से वरिष्ठता का निर्धारण सही स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अभ्यावेदन का निस्तारण ठीक प्रकार से नहीं किया गया।

3. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि वरिष्ठता सूची दिनांक 22.03.2005 अपास्त फरमाई जाये एवं यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गए अभ्यावेदन पर पारित आदेश दिनांक 19.04.2006 अपास्त किया जावे एवं यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 22-12-1983 से वरिष्ठता का लाभ देते हुए समस्त परिणामिक लाभ दिये जाय। विकल्प में दिनांक 1-1-1986 एनेक्चर-2 में अंकित दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जावे अथवा जिस दिनांक से अपीलार्थी के साथ नियुक्त समान तृतीय श्रेणी अध्यापक श्री रामकल्याण शर्मा को वरिष्ठता का लाभ दिनांक 13-9-1988 से प्रदान किया गया है उसी अनुसार अपीलार्थी को दिया जावे।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी की सेवाएं जिला स्थापना समिति द्वारा स्क्रीनिंग आदेश तक अपीलार्थी की सेवाएं जिला स्थापना समिति द्वारा स्क्रीनिंग आदेश कर दिनांक 28-11-1990 के आदेश द्वारा की गई है इसलिए, अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ आदेश जारी करने की दिनांक 28-11-1990 से दिया गया है जो नियमानुसार सही है और वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की वरिष्ठता 484

- नंबर पर नियमानुसार अंकित की गई है। अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि आदेश दिनांक 28.11.1990 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं 31.12.1985 से पूर्व की होने के कारण एवं निर्धारित योग्यता व आयु सीमा के अंतर्गत होने से सेवाएं नियमित की गई थी एवं यह भी स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ 01.01.1986 से देय होगा। उनका तर्क है कि यदि किसी कार्मिक की सेवाएं प्रथम नियुक्ति से नियमित कर दी गई और उक्त आदेश विभाग द्वारा प्रत्याहित नहीं किया गया है तो कार्मिक को वरिष्ठता का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही प्रदान की जावेगी। अपीलार्थी के प्रकरण में अपीलार्थी की नियुक्ति 22-12-1983 के आदेश द्वारा की गई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 24-12-1983 को अध्यापक तृतीय के पद पर प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कार्यग्रहण कर लिया। 31-12-1985 से पूर्व के कार्मिकों के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 11-8-1989 की अनुपालना में आदेश दिनांक 28-11-1990 जारी कर अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित कर दिया गया जबकि अपीलार्थी की 31-12-1985 से पूर्व की सेवाओं को नियमित कर दिया गया तो अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ भी उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 22-12-1983 से प्रदान की जानी चाहिये। विवादग्रस्त आदेश वरिष्ठता सूची दिनांक 22-3-2005 में अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ चयन आदेश जारी करने की तिथि 28-11-1990 से दिया गया है जो कि अनुचित एवं अवैध है।
6. इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि पंचायती राज कर्मचारियों को स्थाई किये जाने हेतु स्क्रीनिंग जिला स्थापना समिति द्वारा कराई गई, जिसके पश्चात् आदेश दिनांक 28.11.1990 के आदेश के द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की गई। अपीलार्थी की सेवाएं नियमित किये जाने की दिनांक से ही अपीलार्थी को वरिष्ठता प्रदान की गई। जो उचित है। अपीलार्थी नियमितिकरण की दिनांक से पूर्व से वरिष्ठता नहीं ले सकता है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ का निर्णय दिनांक 03.07.2017 प्रस्तुत किया है।
7. हमने अपीलार्थी व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की अस्थाई नियुक्ति दिनांक 22.12.1983 को हुई थी। जिसमें यह अंकित था कि उनकी अस्थाई नियुक्ति अध्यापक पद पर शिक्षा सत्रांत 83-84 अथवा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तब तक के लिए वेतन श्रंखला 490-840 में प्राथमिक शाला ढाणी अहिरान, सांभरिया में की

जाती है। यह भी अंकित है कि बिना नोटिस दिये किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो नियुक्ति दिनांक 22.12.1983 को हुई थी, वह नियमित नियुक्ति नहीं थी, बल्कि ad-hoc के रूप में हुई थी। यह भी स्पष्ट है कि बाद में अपीलार्थी की सेवाएं आदेश दिनांक 28.11.1990 के द्वारा जिला स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार नियमित की गई थी। इस बिन्दू पर कोई आपत्ति नहीं है कि राज्य सरकार के अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की गई थी और स्क्रीनिंग के पश्चात जिला स्थापना समिति के आदेश से अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की गई थी।

8. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9,

18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

9. अतः बिन्दू संख्या-1 व 4 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। यह भी माना है कि वरिष्ठता या अन्य लाभ के संबंध में नियमितकरण की दो भिन्न तारिख नहीं हो सकती।
10. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं 28.11.1990 को स्क्रीनिंग के बाद नियमित की गई, उसकी पूर्व की सेवाओं को अपीलार्थी वरिष्ठता व अन्य लाभ के लिए अपनी सेवा अवधि में नहीं जुड़वा सकता है। अतः अपीलार्थी को जो नियमितकरण की दिनांक 28.11.1990 से नियमित मानते हुए उसी दिनांक से वरिष्ठता दी गई। उसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)